(DR. Y.K. ALAGH): (a) As on 31.3.96 there were 8 projects in the public sector which had time overrun of 60% and incurred only 5% or less of their latest approved cost.

(b) and (c) In February 1996, the Government accepted, in principle, the suggestions of the Group of Ministers on specific measures to cut delays in the implementation of central sector projects. One of the suggestions relates to weeding out/transferring to Joint/Private sector of the projects which are making slow progress in various sectors. Broad features of the proposal are that the projects which would be considered for weeding out/transfer are those on which expenditure incurred is 5% or less even after 60% of the gestation is over. List of projects would be drawn up keeping in view the resource crunch and other relevent factors such as the strategic importance of the project, constraints in land acquisition, change in government policies/market conditions, backward and forward linkage, etc. Ministries/ Department have been asked to reprioritise their ongoing projects in the light of the decision of the Government.

(d) No project has been identified under Govt. decision of February, 1996, as yet.

जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान से मिलने वाली सहायता

3826. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा सैन्य और अर्धसैनिक बलों के कितने कार्मिक तथा कितने नागरिक मारे गए;

(ख) क्या सरकार के पास इस बात का कोई सबूत है कि जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान से सहायता मिल रही है; और

(ग) सरकार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) वर्ष 1993 और इसके बाद जम्मू और कश्मीर मे आतंकवादी हिंसा में मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिकों और सिविलियनों की वर्ष-वार संख्या नीचे दर्शाई गई है:

वर्ष	सुरक्षा बल कार्मिक	सिविलियन
1993	195	1057
1994	198	1069
1995	234	1202
1996 (31.8.1996 तक)	106	1028

(ख) यह सत्य है कि पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को चलाने, उसे भड़काने और उसकी मदद करने में सक्रिय रूप से लिप्त रहा है।

(ग) राज्य में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इन प्रयासों में सीमा/नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बढ़ाना, उग्रवादियों को बाहर खदेड़ने के लिए लगातार अभियान चलाना, आसूचना तंत्र को निरंतर सुचारू और सक्रिय बनाना, सुभेद्य और संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेट और गश्त इत्यादि लगाना, शामिल है।

World Bank Assistance for Slum Improvement

3827. SHRI LACHHMAN SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether World Bank has any scheme for financial assistance to States for slum improvement;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any amount has been sanctioned to Punjab, Haryana and Uttar Pradesh for slum improvement; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT. (DR. U. VENKATESWARLU): (a) The World